

समक्ष एच.एस. बेदी और जे.एस. नारंग, माननीय न्यायमूर्ति

अंशुल सूद और अन्य - याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य - प्रतिवादी

C.W.P. 2004 की संख्या 5833

31 अगस्त 2004

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956- धारा 3 - भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 16 अक्टूबर, 2003 जारी- चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 10 फरवरी, 2004- बी.ई. में प्रवेश। पीईसी में डिग्री पाठ्यक्रम - भारत सरकार ने यूजीसी की सिफारिश पर अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत अधिसूचना जारी करते हुए पीईसी-चंडीगढ़ प्रशासन को 10 फरवरी, 2004 की अधिसूचना द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया, जिससे राज्य कोटे की सीटों का आरक्षण कम हो गया। 85% से 50% तक की चुनौती - एक विश्वविद्यालय के रूप में स्वायत्त, प्रशासनिक और वित्तीय रूप से कार्य करने से पहले विभिन्न कार्यों को प्रतिबद्ध करना, पूरा करना और उनका अनुपालन करना आवश्यक है - एसोसिएशन के ज्ञापन को आवश्यक रूप से एक डीम्ड विश्वविद्यालय को कार्यात्मक बनाने से पहले अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। आज तक स्वीकृत - यूजीसी की सिफारिशें 1956 अधिनियम की धारा 3 के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए पूर्व शर्त नहीं हैं - प्रतिवादियों ने स्वीकार किया कि पीईसी को एक डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में चलाने के लिए वास्तव में, तथ्यात्मक और व्यावहारिक रूप से

अंतराल अवधि की आवश्यकता है - चंडीगढ़ प्रशासन यह भी स्वीकार कर रहा है कि एमओए की मंजूरी और कार्यान्वयन के अभाव में पीईसी वर्तमान सत्र के लिए एक डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में पूर्ण परिप्रेक्ष्य में कार्य करने में सक्षम नहीं है। वर्तमान सत्र के दौरान डीम्ड विश्वविद्यालय के कामकाज को व्यावहारिक और तथ्यात्मक रूप से संभव नहीं बनाने के लिए, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित सीटों को कम करने का आदेश टिकाऊ नहीं है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

अभिनिर्धारित कि यह तर्क दिया गया है कि जहां तक पीईसी को डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में दी गई स्थिति का सवाल है, वह चुनौती के अधीन नहीं है, लेकिन, इसे वास्तविक, तथ्यात्मक और व्यावहारिक रूप से कार्य करने के लिए जो कार्य करने या करने की आवश्यकता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी को संबंधित पक्षों को समय की आवश्यकता हो सकती है। यदि ऐसा है, तो डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में पीईसी के व्यावहारिक कामकाज के लिए आवश्यकताओं का अनुपालन किए बिना 10 फरवरी, 2004 को अधिसूचना/आदेश जारी करने की कोई जल्दी नहीं थी। विशेष रूप से, जब चंडीगढ़ प्रशासन का रुख यह है कि चंडीगढ़ के स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण को 85% से घटाकर 50% करना एमओए पर निर्भर है और इसमें निहित है, तो इस संबंध में, पैरा 6 का विशेष संदर्भ दिया गया है। वही, लेकिन, एमओए को अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है। जबकि, चंडीगढ़ प्रशासन इस आधार पर आगे बढ़ रहा है कि एमओए को मंजूरी दे दी गई है जैसा कि लिखित बयान में उनके कथनों में कहा गया है, जो तथ्य गलत है। जब मूल दस्तावेज, जिसके आधार पर रुख को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, तो विवादित आदेश/अधिसूचना जारी करना टिकाऊ नहीं होगा और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि पीईसी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिए जाने के बावजूद, इसके कामकाज को स्वायत्त-वित्तीय और हर तरह से स्वायत्त नहीं बनाया जा सका। बजट में प्रावधानों को एक बार फिर से आवंटित किया गया है। यह अजीब बात है कि चंडीगढ़ प्रशासन को अच्छी तरह से पता था कि एमओए को मंजूरी नहीं दी गई है, जैसा कि उन्हें भारत सरकार से प्राप्त संचार से स्पष्ट है, लेकिन उन्होंने 10 फरवरी, 2004 को आदेश जारी करने का फैसला किया, जिसके आधार पर कोटा का आरक्षण स्थानीय लोगों के लिए 85% से घटाकर 50% कर दिया गया है, जिसे यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए पूर्व-आवश्यकता नहीं दिखाया गया है।

पेरा 32

आगे कहा गया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि 16 अक्टूबर, 2003 की मुख्य अधिसूचना चुनौती के अधीन नहीं है, लेकिन, किसी भी मामले में, यह सभी ने स्वीकार किया है कि डीम्ड विश्वविद्यालय को वास्तव में, तथ्यात्मक और व्यावहारिक रूप से क्रियाशील बनाने के लिए अंतराल अवधि की आवश्यकता होती है। हालाँकि, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा किए गए कृत्यों और दिए गए अनुमानों से पता चलता है कि पीईसी वर्तमान सत्र 2004-05 के लिए एक डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में पूर्ण परिप्रेक्ष्य में कार्य करने में सक्षम नहीं होगा। उन्होंने 8 जुलाई, 2004 की अधिसूचना में बहुत निष्पक्षता से कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2004-05 के लिए पीईसी पंजाब विश्वविद्यालय के तत्वावधान में कार्य करना जारी रखेगा। संबद्धता और शैक्षणिक कार्यक्रमों आदि का उद्देश्य और यह कि डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में नया शैक्षणिक कार्यक्रम अगले शैक्षणिक सत्र 2005-06 से लागू

किया जाएगा। यदि ऐसा है, तो जिस एकान्त कार्य के आधार पर वर्तमान सत्र 2004-05 के लिए स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित सीटें कम कर दी गई हैं, उसे 15 फरवरी, 2004 के आक्षेपित आदेश के आधार पर कम नहीं किया जा सकता था, खासकर तब जब ऐसा किया गया हो। एमओए को मंजूरी दिए बिना जारी किया गया है, जबकि ऐसा आदेश चार्टर यानी एमओए के पैरा 6 पर आधारित है।

पैरा 36

सुयाचिकाकर्ताओं के लिए:- सुश्री निर्मलजीत कौर, अधिवक्ता।

प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के लिए:- श्री एस.के. शर्मा, स्थायी वकील।

प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के लिए:- श्री राजीव आत्मा राम, वरिष्ठ अधिवक्ता और सुश्री सुनीत कौर, अधिवक्ता।

निर्णय

जेएस नारंग, माननीय न्यायमूर्ति

1. यह निर्णय **2004** की सिविल रिट याचिका संख्या **5833, 10590** और **10966** का निपटारा कर देगा, क्योंकि इसमें कानून के सामान्य प्रश्न और कुछ हद तक समान तथ्य शामिल हैं और माँगी गई राहत भी समान है। संक्षिप्तता के लिए, तथ्यों को **2004** की सिविल रिट याचिका संख्या **5833** से लिया जा रहा है।

2. वर्तमान याचिकाओं में शामिल मुद्दा यह है कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (इसके बाद "पीईसी" के रूप में संदर्भित) में सीटें निम्नलिखित तरीके से भरी जा रही थीं:

वर्ष **2003-04** के लिए विभिन्न शाखाओं में बीई डिग्री पाठ्यक्रम में सीटों की कुल संख्या: **385**

सीटों का वितरण इस प्रकार था:-

(a) **85%** - राज्य कोटा (यूटी चंडीगढ़): **329** सीटें

उपरोक्त प्रतिशत के लिए पात्रता यह है कि छात्र ने अपनी योग्यता परीक्षा (10+2) केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ से उत्तीर्ण की हो।

(b) **15%** - अखिल भारतीय कोटा: **56** सीटें

वे अभ्यर्थी जिन्होंने अपनी योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, लेकिन उपरोक्त श्रेणी (ए) के अंतर्गत नहीं आते हैं।

उपरोक्त अनुसार सीटों का विवरण भी प्रदान किया गया है यानी श्रेणी (ए) से **244** सीटों को खुली सीटों के रूप में घोषित किया गया था और **85** सीटों को अनुसूचित जाति, बेटे/बेटियों/सैनिकों के पति/पत्नी जैसी आरक्षित श्रेणियों में रखा गया था। अर्धसैनिक बल के जवान/शारीरिक रूप से विकलांग/स्वतंत्रता सेनानियों और खिलाड़ियों के बच्चे और पोते-पोतियां। इसी प्रकार, **15%** सीटों में से **38** सीटों को खुली सीटों के रूप में रखा गया है और **18** सीटों को आरक्षित श्रेणियों के लिए आरक्षित रखा गया है। हमें पाठ्यक्रमों में विभिन्न शाखाओं में दिए गए विवरण में जाने की आवश्यकता नहीं है।

3. याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि **10** फरवरी, **2004** की अधिसूचना, प्रतिलिपि अनुलग्नक पी-3 के आधार पर, चंडीगढ़ प्रशासन ने राज्य कोटा (यूटी चंडीगढ़) को **85%** से घटाकर **50%** कर दिया है और उक्त कटौती की सीमा तक **35%** अखिल भारतीय कोटा में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसका अर्थ है कि सीटों की उपलब्धता राज्य कोटा और अखिल भारतीय कोटा के मुकाबले **50:50** के अनुपात में की गई है।

4. भारत के संविधान के अनुच्छेद **226/227** के तहत दायर की गई है, जिसमें इस महत्वपूर्ण तर्क के अलावा विभिन्न आधारों पर पूर्वोक्त आदेश को चुनौती दी गई है कि **16** अक्टूबर, **2003** की अधिसूचना के बावजूद पीईसी प्रभावी रूप से "डीम्ड विश्वविद्यालय" नहीं बन पाया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी, प्रतिलिपि अनुलग्नक पी-11 है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस

अधिसूचना की वैधता को किसी भी याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। उपरोक्त अधिसूचना पर ध्यान देना उचित होगा, जो इस प्रकार है :-

क्रमांक एफ.9-38/2001-यू.3

भारत सरकार,

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली 16 अक्टूबर 2003।

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ को तत्काल प्रभाव से मानित विश्वविद्यालय घोषित करती है।

(रवि माथुर)

भारत सरकार के संयुक्त सचिव।

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय, फ़रीदाबाद (हरियाणा)।

प्रति सूचना हेतु अग्रेषित:

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
2. प्रिंसिपल/निदेशक, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ - 160009।

"पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ को डीम्ड विश्वविद्यालय का अनुदान इस शर्त के अधीन है कि वह डीम्ड विश्वविद्यालयों पर लागू यूजीसी और

एआईसीटीई द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों/निर्देशों का पालन करेगा।"

3. गृह सचिव-सह-शिक्षा सचिव, शिक्षा विभाग, चंडीगढ़

प्रशासन यूटी सचिवालय, सेक्टर-9, चंडीगढ़-160009।

4 से 11

XX XX XX XX "

(6) याचिकाकर्ताओं की यह दलील है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (संक्षेप में यूजीसी अधिनियम) की धारा 3 के तहत एक संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित करके, एक विशेष स्थापित प्रक्रिया और कई उक्त संस्थान को तथ्यात्मक रूप से और वास्तव में एक डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करने की अनुमति देने से पहले औपचारिकताओं का अनुपालन और पूरा किया जाना आवश्यक है, जो इस प्रकार हैं: -

"(ए) संस्थान को स्वायत्त होना चाहिए। यानी इसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम या सार्वजनिक ट्रस्ट अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए और यूजीसी द्वारा निर्धारित मॉडल के आधार पर एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और नियम तैयार करना चाहिए।

(b) मानित विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता चाहने वाले संस्थान के नाम पर चल और अचल संपत्ति कानूनी रूप से निहित होनी चाहिए।

(c) मानित विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता चाहने वाले संस्थान में सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश 50% के अनुपात में किया जाएगा: राज्य कोटा (यूटी) के लिए 50% (वर्तमान मामले में चंडीगढ़ कोटा) छात्र और अखिल भारतीय कोटा छात्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा या यूजीसी द्वारा पहचानी और अनुमोदित संस्था/एजेंसी द्वारा आयोजित एक सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से।

(d) डीम्ड के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उपरोक्त योग्यता रखने वाला संस्थान

विश्वविद्यालय को इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सरकार के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को भारत के, यूजीसी द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा पर आवेदन करना आवश्यक है।

(e) यूजीसी द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद आवश्यक निरीक्षण और सत्यापन करने के लिए संस्थान का दौरा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाती है। समिति मामले में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए अपनी रिपोर्ट यूजीसी को सौंपती है। यूजीसी की बैठक में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया जाता है। इसके बाद, यूजीसी की सिफारिश, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को मानद विश्वविद्यालय घोषित करने के लिए सरकार को भेज दी जाती है।

(f) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, यूजीसी की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में अधिसूचित करती है।

(g) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के उपरोक्त अधिसूचना जारी होने के बाद, संबंधित राज्य सरकार। (पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के तत्काल मामले में चंडीगढ़ प्रशासन) को संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में संचालित करने के लिए एक अधिसूचना जारी करने और/या एक विस्तृत आदेश पारित करने की आवश्यकता है।

(h) राज्य सरकार (पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के तत्काल मामले में चंडीगढ़ प्रशासन) की अधिसूचना जारी होने और/या विस्तृत आदेश पारित होने के बाद, संस्थान निम्नलिखित सहित परिणामों के साथ एक डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में काम करना शुरू कर देता है:

(i) संस्थान के डीम्ड विश्वविद्यालय बनने के साथ, सभी चल और अचल संपत्तियां संस्थान के नाम पर स्थानांतरित हो जाती हैं और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के तत्काल मामले में चंडीगढ़ प्रशासन के पास निहित नहीं रहती हैं।

(ii) सोसायटी/ट्रस्ट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के प्रशासनिक नियंत्रण में आ जाती है, जिसे यूजीसी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव भेजते समय मेमोरेंडम

ऑफ एसोसिएशन में निर्दिष्ट किया गया है। मौजूदा मामले में, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं रहता है।

(iii) एक विश्वविद्यालय की तरह, संस्थान द्वारा प्रस्तावित सभी स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं संस्थान द्वारा ही आयोजित की जाती हैं। संस्थान अपने पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के संचालन और उसके लिए डिग्री प्रदान करने के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं रहता है।

(iv) हालाँकि संस्थान की फंडिंग एजेंसी अभी भी वही है जो इसे एक मानित विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता देने से पहले थी, फिर भी संस्थान के लिए सरकार की तरह कोई वार्षिक बजट आवंटन नहीं किया जाता है। इसके बजाय, संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) के लिए अनुदान सहायता उसी फंडिंग स्रोत द्वारा स्वीकृत की जाती है जिसने संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय बनने से पहले वार्षिक बजट आवंटित किया था।

(v) एक कॉलेज के विपरीत, एक डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थान का नेतृत्व एक कुलपति या एक निदेशक द्वारा किया जाता है, न कि एक प्रिंसिपल द्वारा।

(vi) शैक्षणिक मामलों से संबंधित सभी नीतिगत निर्णय, जिसमें अध्ययन बोर्ड का गठन, अनुसंधान बोर्ड का गठन, अनुसंधान डिग्री समितियों का गठन, संस्थान की डिग्री और प्रमाणपत्रों का डिजाइन आदि शामिल हैं, संस्थान की सीनेट द्वारा लिए जाते हैं, न कि उस विश्वविद्यालय द्वारा, जिससे संस्थान जुड़ा है। मानित विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता से पहले संबद्ध था।

(vii) एक कॉलेज के विपरीत, एक डीम्ड विश्वविद्यालय के लिए एक रजिस्ट्रार नियुक्त किया जाता है।

(viii) राज्य सरकार के कॉलेज के विपरीत (चंडीगढ़ प्रशासन के तहत पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के तत्काल मामले में) संकाय की भर्ती संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा विधिवत गठित चयन समितियों द्वारा की जाती

है। यानी संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के माध्यम से संकाय की भर्ती को संस्थान के डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में संचालन शुरू होते ही बंद कर दिया जाता है।

(ix) एक सरकार के विपरीत. विभाग गैर-शिक्षण समूह 'सी' और 'डी' पदों के लिए भर्ती संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा विधिवत गठित चयन समितियों द्वारा की जाती है, न कि क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से, जो कि सरकार में प्रथा है। "

7. यह कहा गया है कि पीईसी को एक डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन इसे एक डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में संचालित करने के लिए तस्वीर स्पष्ट नहीं है। इससे पहले कि इसे सही और सही परिप्रेक्ष्य में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में स्वीकार किया जा सके, बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, पीईसी अभी भी चंडीगढ़ प्रशासन के नियंत्रण में एक सरकारी विभाग के रूप में कार्य कर रहा है, जो कि यूजीसी अधिनियम की धारा 3 के तहत अधिसूचना जारी होने से पहले की स्थिति थी। यदि ऐसा है, जिसे व्यवहारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है, तो चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2004, प्रतिलिपि अनुलग्नक पी-3 जारी किया जाना न तो उचित है और न ही कानून के तहत टिकाऊ है।

8. इस संबंध में, यह भी कहा गया है कि पीईसी एक सरकारी विभाग के रूप में काम कर रहा है, जो तथ्य चंडीगढ़ प्रशासन के कृत्यों यानी दिनांकित एक पत्र से स्थापित होता है। 30.1.2004 को चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली मसौदा अधिसूचना की मंजूरी के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को संबोधित किया गया था। इस संबंध में अभी तक कोई मंजूरी नहीं मिली है। पत्र की प्रति संलग्नक पी-4 के रूप में संलग्न की गई है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह अभ्यास यूजीसी अधिनियम की धारा 3 के तहत अधिसूचना जारी होने से पहले किया जाना आवश्यक है या डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में स्थिति पेश करने के लिए कहीं भी ऐसी कोई अनुवर्ती कार्रवाई प्रदान की जाती है। अनुबंध पी-4 के भाग के रूप में संलग्न मसौदा अधिसूचना के अवलोकन से पता चलता है कि प्रशासन अपने मन में स्पष्ट नहीं है कि पीईसी किस तारीख से वास्तव में,

तथ्यात्मक और व्यावहारिक रूप से एक डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा। इस संबंध में मसौदा अधिसूचना के कुछ पैराग्राफों पर ध्यान देने की जरूरत है, जो इस प्रकार हैं:-

"3. 1 मार्च 2004 से, कॉलेज को सोसायटी में स्थानांतरित करने से पहले कॉलेज के विभिन्न विभागों/अनुभागों के लिए चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा स्वीकृत सभी पद सोसायटी को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे।

4(i) 1.3.2004 से पहले की अवधि के लिए, अधिकारी, शिक्षक या अन्य कर्मचारी, जो या तो कॉलेज को सोसाइटी में स्थानांतरित करने से पहले पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में तैनात थे या तैनात होने के लिए उत्तरदायी थे, काम करना जारी रखेंगे। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा तय किए गए समय तक, ऐसे काम के लिए किसी विशेष भत्ते के बिना, अपने-अपने पदों पर बने रहेंगे।

(ii) पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के कर्मचारियों को पहले से ही पंजीकृत पीईसी सोसाइटी में शामिल होने या सरकारी कर्मचारी बने रहने (प्रशासन में कहीं और उनके कैडर में रिक्त पदों के विरुद्ध समायोजित किए जाने के लिए) के संबंध में एक राय दी जाएगी। उन्हें यह स्पष्ट कर दिया जाएगा कि यदि उनके संबंधित कैडर में ऐसे कोई रिक्त पद उपलब्ध नहीं हैं तो उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा।

XX XX XX XX

(v) पीईसी के वर्तमान कर्मचारी जो पीईसी सोसायटी में शामिल होने का विकल्प चुनते हैं, वे **1.3.2004** से पीईसी सोसायटी के कर्मचारी बन जाएंगे और सरकारी कर्मचारी नहीं रहेंगे। सोसायटी को सरकारी कर्मचारियों के आवंटन की तिथि से, आवंटित व्यक्तियों को वेतन, भत्ते, ऋण, अग्रिम और अन्य स्वीकार्य रियायतों के भुगतान की जिम्मेदारी कॉलेज द्वारा वहन की जाएगी। सोसायटी ऐसे आवंटित व्यक्तियों से जीपी फंड और बचत-सह-समूह बीमा योजना के लिए उनके योगदान की वसूली करेगी और उसे चंडीगढ़ प्रशासन के उचित लेखा प्रमुख के रूप में जमा करेगी।

XX XX XX XX

6. जब तक चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता है, यूनिट मुख्य अभियंता, यूटी, चंडीगढ़ कॉलेज परिसर में इमारतों, सड़कों, विद्युत प्रतिष्ठानों, जल आपूर्ति, सीवेज निपटान और जल निकासी से संबंधित सभी रखरखाव कार्यों में भाग लेना जारी रखेंगे। मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार. चंडीगढ़ प्रशासन ऐसे कार्यों के लिए मुख्य अभियंता, यूटी चंडीगढ़ को आवश्यक धनराशि आवंटित नहीं करेगा। मुख्य अभियंता, यू.टी., चंडीगढ़ 1 मार्च, 2004 के बाद सोसायटी द्वारा अनुरोध किए गए सभी अतिरिक्त निर्माण/स्थापना कार्यों को जमा कार्य के आधार पर बिना कोई स्थापना लागत वसूल किए निष्पादित करेगा।

XX XX XX XX XX

9. चालू वर्ष के लिए, पीईसी संबद्धता और शैक्षणिक कार्यक्रमों आदि के उद्देश्य से पंजाब विश्वविद्यालय के तत्वावधान में कार्य करना जारी रखेगा। एक डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में पीईसी के नए शैक्षणिक कार्यक्रम अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2004-2005 से लागू किए जाएंगे। एनआरआई सीटों/एनआरआई प्रायोजित सीटों की शुरुआत और छात्रों के लिए ट्यूशन फीस में संभावित वृद्धि की संभावना के संबंध में मामला पीईसी सोसायटी पर छोड़ दिया जाएगा।

XXX XXX XXX XXX |"

9. उपरोक्त के अवलोकन से पता चलता है कि डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में पीईसी के नए शैक्षणिक कार्यक्रमों को अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2004-05 (वर्तमान सत्र) से लागू करने का प्रस्ताव था।

10. ऐसा लगता है कि सरकार पीईसी को एक डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करने की स्थिति में नहीं थी, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि अनुदान सहायता, जिसे पहले पीईसी की स्थापना के समय चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा स्वीकृत किया गया था। वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान डीम्ड विश्वविद्यालय बनने के लिए बजट आवंटन में शामिल किया गया है। जबकि, 16 फरवरी 2004 के पहले पत्र में पीईसी को सूचित किया गया था कि वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए पीईसी के लिए कोई बजट उपलब्ध नहीं कराया गया है। जबकि, 29 मार्च 2004 की बाद की अधिसूचना के माध्यम

से, वित्तीय विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन ने तदनुसार धन आवंटित करने के लिए वित्तीय वर्ष **2004-05** (वर्तमान सत्र) के लिए बजट प्रावधान को संशोधित किया।

11. यह भी कहा गया है कि संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के नियंत्रण में एक निदेशक नियुक्त करना उत्तरदाताओं के लिए अनिवार्य था, जो डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। लेकिन आज तक उत्तरदाताओं द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है, जैसा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संबोधित **6** फरवरी, **2004** के संचार, प्रतिलिपि अनुलग्नक पी-8 से स्पष्ट है, जिसमें यह किया गया है उल्लेख किया गया है कि आयोग की मंजूरी से अवगत कराते समय, दिनांक **3** जुलाई, **2003** के पत्र के माध्यम से, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि **(1)** कॉलेज की शासन संरचना आईआईटी (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान) **(2)** के समान होनी चाहिए। भर्ती सुविधाएं आईआईटी पैटर्न पर आधारित हो सकती हैं जैसा कि एनआईटी संस्थानों **(3)** में किया गया है। संस्थान का पहला निदेशक अधिमानतः आईआईटी प्रणाली से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए।

12. यह भी देखा जा सकता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के संबंध में केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश भेजते समय पाया था कि पीईसी द्वारा प्रस्तुत मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) मॉडल मेमोरेंडम के अनुरूप नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित एसोसिएशन। एक और अनुरोध किया गया था कि पीईसी के एमओए को पैटर्न के अनुसार अंतिम रूप दिया जाए। यह स्पष्ट है कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत एमओए को यूजीसी अधिनियम की धारा **3** के तहत जारी अधिसूचना से पहले न तो अंतिम रूप दिया गया था और न ही स्वीकार किया गया था। इसी कारण से पीईसी की डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में स्पष्ट स्थिति समझ में नहीं आ रही थी। एक अन्य कारक जिसका उल्लेख किया गया है, वह है, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा **2003** की सिविल रिट याचिका संख्या **17643** में दायर लिखित बयान, जिसमें एक स्पष्ट दलील दी गई है कि अधिसूचना दिनांक

16.10.2003, सरकार द्वारा जारी की गई है लेकिन कॉलेज अभी भी चंडीगढ़ प्रशासन के एक विभाग के रूप में कार्य कर रहा है और पीईसी के एमओए को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना बाकी है। इसके अलावा, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन अभी भी नहीं किया गया है और जब तक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा इसमें बदलाव नहीं किया जाता है तब तक कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु **58** वर्ष ही रहेगी। दलील यह भी है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के नियम और शर्तें अभी भी खामोश हैं। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि तदनुसार सीटों के आवंटन को आरक्षित करने की आवश्यकता पीईसी के एमओए में निहित है, जिसे चंडीगढ़ प्रशासन के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना बाकी है। यहां यह देखा जा सकता है कि इस याचिका पर चंडीगढ़ प्रशासन ने यह रुख अपनाया है कि भारत सरकार द्वारा दिनांक **16.10.2003** को अधिसूचना जारी करने के मद्देनजर, पीईसी को सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। कार्यान्वयन जो पूर्वोक्त अधिसूचना के अनुसार किया जाना है। जहां तक **2003** की सिविल रिट याचिका संख्या **17643** में इसके द्वारा अपनाए गए रुख का सवाल है, यह कहा गया है कि लिखित बयान में दिए गए बयान अनजाने में हुई गलतियों के अलावा कुछ नहीं हैं और सही तथ्यों को शामिल करते हुए संशोधित लिखित बयान दायर किया जा रहा है।

13. यह भी कहा गया है कि किसी संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित करने का उद्देश्य उसे प्रशासनिक, वित्तीय और शैक्षणिक रूप से स्वतंत्र बनाना है, जो कि पीईसी के संबंध में अब तक पूरा नहीं हुआ है। कहने की जरूरत नहीं है कि पीईसी को एक विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करने के लिए स्वायत्त निकाय/संस्था के रूप में नकारा नहीं जा सकता है। यूजीसी अधिनियम की धारा **3** के तहत अधिसूचना जारी करना सभी दृष्टिकोणों से संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय मानने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे संस्थानों में जिन छात्रों को अभी प्रवेश दिया जाना है और जो वहां पढ़ रहे हैं, उनके जीवन से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। अधिकारियों द्वारा अपनाए गए ढुलमुल रवैये से शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि समाज को ऐसे अनुमान दिए जाने से पहले किसी ने भी होमवर्क पूरा नहीं किया है।

12. याचिका के पैरा **14** में कहा गया है कि पीईसी की आरक्षण नीति, जिसके तहत चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा प्रस्तुत मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) को मंजूरी देने के लिए बदलाव को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है, को अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है। यह एमओए का पैरा **6** है, जिसमें यह निहित है कि स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए **50%** सीटें अखिल भारतीय आधार पर भरी जाएंगी। यह स्पष्ट है कि एमओए की मंजूरी पर, आरक्षण का यह अधिकार तदनुसार प्रवाहित होगा। यह कहा गया है कि उक्त एमओए को अभी तक भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। हमारे लिए भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा प्रस्तुत पैरा **14** के उत्तर का अध्ययन करना आवश्यक हो गया है। भारतीय संघ का रुख यह है कि **50:50%** के आधार पर प्रवेश की नीति का पालन उस तारीख से किया जाना चाहिए जिस दिन पीईसी को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था और मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन को पहले ही मंजूरी दे दी गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एमओए की मंजूरी के संबंध में एक स्पष्ट रुख अपनाया है और बहुत सतर्क रुख अपनाया है कि एमओए की औपचारिक मंजूरी के अभाव में भी **50:50%** आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। यह भी कहा गया है कि पीईसी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का संचालन शुरू करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा कोई और अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह चंडीगढ़ प्रशासन का रुख यह है कि भारत सरकार ने एमओए को मंजूरी दे दी है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से निहित है कि संस्थान में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश एक सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा और कम से कम **50%** सीटें होंगी जो अखिल भारतीय आधार पर भरी जाएंगी और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए **100%** सीटें अखिल भारतीय आधार पर भरी जाएंगी। इसलिए, एमओए के अनुसार भी न्यूनतम **50%** सीटें अखिल भारतीय आधार पर भरी जानी हैं। पैरा **14** के उत्तर में, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रस्ताव के साथ एमओए यूजीसी/भारत सरकार को भेजा गया था और **16** अक्टूबर, **2003** को यूजीसी अधिनियम की धारा **3** के तहत अधिसूचना जारी करने के समय इसे मंजूरी दे दी गई है।

15. प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 के संबंधित उत्तरों पर ध्यान देना उचित होगा जो इस प्रकार हैं:

याचिका का पैरा 14 :

"**14.** पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए आरक्षण नीति एमओए के पृष्ठ 4 पर पैरा 6 में प्रदान की गई है, जिसमें कहा गया है कि सभी स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए 50% सीटें अखिल भारतीय आधार पर भरी जाएंगी, जिसका अर्थ है कि यह नीति पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए आरक्षण तभी लागू किया जा सकता है जब यह एक डीम्ड विश्वविद्यालय बन जाए और संचालित हो। हालाँकि, एमओए, जो 50:50% आरक्षण नीति प्रदान करता है, को अभी तक भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है जैसा कि कहा गया है चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने लिखित बयान दिनांक 11.3.2004 (अनुलग्नक पी-9) में कहा, इसलिए, सरकार की मंजूरी के अभाव में, राज्य कोटा (चंडीगढ़ कोटा) के छात्रों और अखिल भारतीय कोटा के छात्रों के लिए मौजूदा नीति (85%:15%) को संशोधित करने के लिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है। मोरेसो, जब याचिकाकर्ताओं ने 85%:15% की मौजूदा आरक्षण नीति का लाभ लेने के लिए चंडीगढ़ के स्कूलों/कॉलेजों में 10+2 में प्रवेश ले लिया है, तो प्रवेश प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। इसे केवल तभी संशोधित किया जा सकता है जब पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज अपने एमओए और चंडीगढ़ प्रशासन की मसौदा अधिसूचना को सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में काम करना शुरू कर देगा। भारत सरकार और इस संबंध में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा एक अंतिम अधिसूचना जारी की गई है।"

प्रतिवादी संख्या 1 के पैरा 14 का उत्तर

"**14.** पैरा 14 के उत्तर में, यह प्रस्तुत किया गया है कि 50:50 के आधार पर प्रवेश के लिए नीति का पालन उस दिन से किया जाना चाहिए जिस दिन पीईसी को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था, दूसरी बात, जैसा कि ऊपर बताया गया है, एमओए को पहले ही मंजूरी दे दी गई है।"

प्रतिवादी क्रमांक 2 के पैरा 14 का उत्तर

एमओए की मंजूरी के अभाव में भी **50:50** आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता का पालन किया जाना है। हालांकि, यह फिर से दोहराया गया है कि आगे जारी करना डीम्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन का संचालन शुरू करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अधिसूचना की आवश्यकता नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के पैरा 14 का उत्तर :

14. ऊपर बताए गए तथ्यों और प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए अस्वीकार कर दिया गया। मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन को प्रस्ताव के साथ यूजीसी/भारत सरकार को भेजा गया था और इसे सरकार द्वारा अधिसूचना अनुलग्नक आर-2 जारी करने के साथ अनुमोदित किया गया है। पहले पैराग्राफ में प्रस्तुत तथ्यों को इस पैराग्राफ के उत्तर में पढ़ा जा सकता है।"

16. बहस के दौरान, भारत संघ और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वकील के माध्यम से प्रासंगिक रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया गया था, जिसके आधार पर यूजीसी की धारा 3 के तहत अधिसूचना जारी की गई थी। अधिनियम दिनांक 16 अक्टूबर, 2003 को यू.जी.सी. की अनुशंसा पर जारी किया गया था। और यू.जी.सी. की सिफारिशों का स्पष्ट संदर्भ। दोनों उत्तरदाताओं ने संपूर्ण रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जिसका हमने अवलोकन किया है। हम फैसले के बाद के हिस्से में एमओए को मंजूरी देने की स्थिति पर वापस लौटेंगे। यू.जी.सी. द्वारा 3 जुलाई, 2003 के पत्र के माध्यम से की गई सिफारिश पर ध्यान देना उचित होगा, जिसकी प्रति यू.जी.सी. के लिखित बयान के साथ अनुलग्नक आर 2/1 के रूप में संलग्न की गई है। आयोग के कार्यवृत्त और संकल्प को पूर्वोक्त संचार में पुनः प्रस्तुत किया गया है जो इस प्रकार है:-

"XXX XXX XXX XXX

आयोग ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। आयोग ने आगे निर्णय लिया कि विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों को पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा जाएगा, जो नीचे दर्शाया गया है: -

- (a) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा **100%** वित्त पोषण के साथ कॉलेज को 'केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान' कहा जाएगा।
- (b) संस्थान की प्रशासनिक संरचना आईआईटी के समान होनी चाहिए। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अध्यक्ष एक शिक्षाविद् या उद्योगपति होना चाहिए।
- (c) यूजी स्तर की **50%** सीटें और पीजी स्तर की **100%** सीटें राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के माध्यम से भरी जा सकती हैं।
- (d) संकायों की भर्ती आईआईटी पैटर्न पर आधारित हो सकती है जैसा कि एनआईटी संस्थानों में किया गया है। साथ ही संस्थान में लचीली कैडर प्रमोशन प्रणाली होनी चाहिए।
- (e) संस्थान का पहला निदेशक अधिमानतः आईआईटी प्रणाली से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए।

विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट/सिफारिश और एमओए /नियमों की एक प्रति आपके त्वरित संदर्भ के लिए यहां संलग्न है। इसके अलावा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से इस संबंध में शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

आपका विश्वासी

हस्ताक्षर/-

(शरणजीत सिंह)

उप कुल सचिव।"

17. इस संचार को भारत संघ द्वारा अपने संक्षिप्त उत्तर में भी संदर्भित किया गया है जब यह निर्देश दिया गया था कि प्रतिवादी नंबर **1** को याचिका का पैरावाइज उत्तर दाखिल करना चाहिए जो बाद में **13** अगस्त, **2004** को दायर किया गया था। भारत संघ ने सिफारिश प्राप्त होने पर **24** जुलाई **2003** के संचार के माध्यम से पीईसी को वापस भेज दी गई, प्रतिलिपि अनुलग्नक आर-**1/2**, जिसके तहत, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)

द्वारा की गई टिप्पणियों को सूचित किया गया था। एआईसीटीई ने स्पष्ट टिप्पणी की कि "कोई भी कार्यक्रम मान्यता प्राप्त नहीं है" और यूजीसी ने सिफारिश की थी कि उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर पीईसी चंडीगढ़ को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। पीईसी की टिप्पणियां मांगी गई थीं और एक स्पष्ट अवलोकन किया गया था कि एमओए /नियमों को भी तदनुसार संशोधित किया जाए। चंडीगढ़ प्रशासन ने 9 सितंबर, 2003 को एक पत्र लिखा था, प्रतिलिपि अनुलग्नक आरआई/III। यह सूचित किया गया था कि एआईसीटीई द्वारा सुझाए गए अनुसार पीईसी द्वारा संचालित प्रत्येक कार्यक्रम को मान्यता देने के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई थी। यूजीसी के दृष्टिकोण से भी सहमति का संकेत दिया गया था। जहां तक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर स्नातक स्तर पर 50% सीटें भरने का सवाल है, चंडीगढ़ प्रशासन ने संकेत दिया कि उन्हें पहले ही मंजूरी दे दी गई थी। यह भी बताया गया था कि एमओए /नियमों को मौजूदा नाम के साथ संशोधित किया गया है और इन्हें जल्द से जल्द अनुमोदन और अधिसूचना जारी करने के लिए संलग्न किया गया था।

18. उत्तरदाताओं का समग्र रुख यह रहा है कि अखिल भारतीय आधार पर स्नातक पाठ्यक्रमों के स्तर पर 50% की सीमा तक सीटों का आरक्षण, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के माध्यम से भरा जाना है, जो सत्र यानी 2004-05 के लिए तदनुसार आयोजित किया जाएगा। उत्तरदाताओं का यह भी रुख है कि पीईसी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा तो दे दिया गया है लेकिन इसे व्यावहारिक रूप देने और इसके कार्यान्वयन में समय लगता है क्योंकि कुछ पूर्तियाँ तदनुसार की जानी हैं। इस प्रकार, संचयी दृष्टिकोण यह है कि पीईसी को एक डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में वास्तव में, तथ्यात्मक और व्यावहारिक रूप से चलाने के लिए कुछ अंतराल अवधि की आवश्यकता होती है। संबंधित प्राधिकारियों को अधिसूचना आदि के माध्यम से अभी भी कुछ कार्यक्रम जारी करने होंगे। ऐसे प्राधिकारियों को तदनुसार अस्तित्व में आना होगा। यूजीसी ने पहले एक संक्षिप्त उत्तर प्रस्तुत करते हुए यह रुख अपनाया था कि पीईसी पर डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए भारत सरकार को सिफारिश भेजते समय लगाई गई शर्तों में से एक यह थी कि स्नातक स्तर पर 50% सीटें और 100% सीटें होंगी। स्नातकोत्तर स्तर को

राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के माध्यम से भरा जा सकता है। हालाँकि, पैरावाइज उत्तर प्रस्तुत करते समय, दलील दी गई कि राज्य कोटा (चंडीगढ़ यूटी कोटा) और अखिल भारतीय कोटा स्थिति के अनुपात को **85%** से **50%: 50%** में बदलना आवश्यक है। यूजीसी के पैरावाइज उत्तर से पता चलता है कि पीईसी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए सिफारिश की गई थी, लेकिन दिनांक **3.7.2003** के पत्र में बताई गई पूर्व-आवश्यकताओं के अनुपालन पर। इसके बाद पीईसी को उनकी टिप्पणियों के लिए एक पत्र भेजा गया था और उसी समय एमओए को अद्यतन करना भी आवश्यक हो गया था। उस पत्र पर चंडीगढ़ प्रशासन के जवाब से पता चलता है कि वे यूजीसी द्वारा भारत सरकार को अनुशंसित पत्र में बताई गई आवश्यकताओं से सहमत थे, लेकिन अधिसूचना जारी होने से पहले अनुपालन किया गया था या नहीं। **16 अक्टूबर 2003** के यूजीसी अधिनियम की धारा **3** के अनुसार, कोई भी उत्तरदाता हमें इस संबंध में कोई प्रयास नहीं दिखा सका है और न ही उनके संबंधित लिखित बयानों में कोई स्पष्ट उत्तर दिया गया है। जहां तक एमओए की मंजूरी का सवाल है, रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि मॉडल एमओए चंडीगढ़ प्रशासन को सूचित किया गया था और जब इसे प्रख्यापित किया गया और उनकी टिप्पणियों के अनुसार यूजीसी को भेजा गया, तो यह अनुरूप और सह-नहीं था। इस संबंध में यूनियन ऑफ इंडिया की अपेक्षित फाइल हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे हमने देखा है। फ़ाइल की कुछ टिप्पणियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि सरकार या किसी ने भी किसी विशेषाधिकार का दावा नहीं किया है और किसी भी मामले में हमारी राय के अनुसार, ऐसे किसी विशेषाधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है, इसे इस प्रकार पढ़ें :

-

" फ़ाइल संख्या **F-9-38/2001-U3** का नोटिंग भाग

एमओए और नियमों की यूजीसी द्वारा जांच की गई और यूजीसी मॉडल एमओए /नियम, आईआईआईटी, इलाहाबाद एमओए /नियम और पीईसी के एमओए /नियमों का तुलनात्मक विवरण **10 जून, 2002** को आयोजित आयोग की बैठक में विचार के लिए रखा गया था।

इन एमओए /नियमों की मोटे तौर पर दोबारा जांच की गई है और स्थिति का सारांश नीचे दिया गया है:

ए. प्रवेश :

यूजीसी मॉडल एमओए ,: यूजीसी या यूजीसी द्वारा पहचानी और अनुमोदित एजेंसी या यूजीसी द्वारा पहचानी और अनुमोदित एजेंसी द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश।

आईआईटी, इलाहाबाद - केंद्र सरकार की नीति के अनुसार प्रवेश।

पीईसी प्रवेश सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से और अखिल भारतीय आधार पर कम से कम **50%** सीटें (खंड 6) (यूजीसी ने सुझाव दिया है कि यूजी स्तर पर **50%** सीटें और पीजी स्तर पर **100%** सीटें राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के माध्यम से भरी जानी चाहिए) पृष्ठ **120/सी**

बी. समीक्षा एवं निरीक्षण :

केंद्र सरकार/यूजीसी/चंडीगढ़ प्रशासन संस्थान के काम और प्रगति की समीक्षा करने और मामलों की जांच करने के लिए एक या अधिक व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है (खंड 7)।

सी. बोर्ड ऑफ गवर्नर्स :

(i) एमओए /नियमों में कुलपति अध्यक्ष होते हैं। आईआईटी, इलाहाबाद और एनआईटी में, केंद्र सरकार द्वारा नामित जाने-माने टेक्नोलॉजिस्ट/इंजीनियर/उद्योगपति/शिक्षाविद् अध्यक्ष होते हैं।

पीईसी, चंडीगढ़ में, प्रशासक यूटी चंडीगढ़ के सलाहकार पहले बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष हैं। बाद के बीओजी में, प्रशासन द्वारा एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद्/उद्योगपति का अध्यक्ष के रूप में चयन किया जाएगा ।

(ii) भारत सरकार/यूजीसी नामांकित व्यक्ति - यूजीसी मॉडल एमओए /नियमों के साथ-साथ आईआईआईटी, इलाहाबाद और एनआईटी में, भारत सरकार (एचआरडी मंत्रालय) के एक नामित व्यक्ति और अध्यक्ष यूजीसी के एक नामित व्यक्ति का प्रावधान है। पीईसी, चंडीगढ़ की पहली बीओजी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बाद के बीओजी में, एक नामांकित व्यक्ति एम/ओ एचआरडी और यूजीसी का प्रावधान है।

डी. वित्त समिति :

एमओए /नियमों में , एम/ओ एचआरडी और यूजीएस प्रत्येक से एक नामांकित व्यक्ति का प्रावधान है।

एनआईटी में भारत सरकार के दो नामांकित व्यक्तियों का प्रावधान है।

पीईसी में भारत सरकार/एम/ओ एचआरडी नामांकित व्यक्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

ई. निदेशक (वीसी के समकक्ष):

एमओए /नियमों के अनुसार कुलपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक खोज समिति द्वारा सुझाए गए 3 नामों के पैनल से की जानी है, जिसमें संस्थान/राज्य या केंद्र सरकार के अध्यक्ष/यूजीसी के अध्यक्ष में से प्रत्येक का एक नामांकित व्यक्ति शामिल होता है।

एनआईटी में निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जानी है।

पीईसी में निदेशक की नियुक्ति चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा खोज समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें प्रशासक, चंडीगढ़ के सलाहकार, सचिव, चंडीगढ़ और केंद्र सरकार और यूजीसी के एक-एक प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

एफ. उपनियमों में परिवर्तन/संशोधन एवं परिवर्धन:

एमओए /नियम और एनआईटी/नियम के अनुसार - संशोधन भारत सरकार की सहमति प्राप्त होने पर प्रभावी होंगे।

पीईसी में संशोधन चंडीगढ़ प्रशासन की सहमति प्राप्त होने पर प्रभावी होंगे।

(3) एमओए /पीईसी के नियमों में से कुछ प्रावधान मॉडल एमओए /यूजीसी या एनआईटी/ एमओए /नियमों के मॉडल एमओए/नियमों के अनुसार नहीं हैं और इनमें संशोधन की आवश्यकता है। निम्नलिखित सुझाव विचार हेतु प्रस्तुत हैं:-

(i) खंड **10** में प्रथम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का प्रावधान हटाया जा सकता है। **80** साल पुराने इस संस्थान में, मौजूदा व्यवस्था तब तक जारी रह सकती है जब तक कि चंडीगढ़ प्रशासन के एक विभाग से पीईसी सोसायटी को पीईसी के हस्तांतरण के लिए अधिसूचना जारी नहीं हो जाती और उसके बाद उपनियमों के नियम **5** में बीओजी का तुरंत गठन किया जा सकता है।

(ii) वित्त समिति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी के एक-एक नामित व्यक्ति को शामिल किया जा सकता है।

(iii) एमओए /नियमों में परिवर्तन/संशोधन और परिवर्धन भारत सरकार की मंजूरी/सहमति प्राप्त होने पर प्रभावी होना चाहिए।

(iv) जहां तक पीईसी, चंडीगढ़ के एमओए /नियमों में प्रवेश, समीक्षा और निरीक्षण और अन्य प्रावधानों का संबंध है, हमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती है।

(4) यदि अनुमोदित हो, तो चंडीगढ़ प्रशासन को सूचित किया जा सकता है कि पीईसी, चंडीगढ़ के एमओए /नियमों के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और एमओए /नियमों की फिर से जांच की गई है। उपरोक्त पैरा **3** में दिए गए सुझाव को आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित किया जा सकता है। यदि आवश्यक समझा जाए तो एमओए /नियमों में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में चर्चा के लिए चंडीगढ़ प्रशासन के एक प्रतिनिधि को बुलाया जा सकता है।

एसडी/-

18.6.2004

XX XX XX

19. एमओए नियमों का अध्ययन करते समय यह देखा गया कि एमओए /पीईसी के नियमों में कुछ प्रावधान यूजीसी के एमओए /नियमों या एनआईटी के एमओए /नियमों के अनुसार नहीं हैं। चंडीगढ़ प्रशासन को इस मंत्रालय के पत्र दिनांक **28.6.2004** द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित सुझावों से अवगत कराया गया :-

(i) खंड 10 में प्रथम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का प्रावधान हटाया जा सकता है। मौजूदा व्यवस्था तब तक जारी रह सकती है जब तक कि चंडीगढ़ प्रशासन के एक विभाग से पीईसी सोसायटी को पीईसी के हस्तांतरण के लिए अधिसूचना जारी नहीं हो जाती और उसके बाद उपनियमों के नियम 5 में प्रस्तावित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का तुरंत गठन किया जा सकता है।

(ii) वित्त समिति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी के एक-एक नामित व्यक्ति को शामिल किया जा सकता है।

(iii) एमओए /नियमों में परिवर्तन/संशोधन और परिवर्धन भारत सरकार की मंजूरी/सहमति प्राप्त होने पर प्रभावी होना चाहिए।

2. इस मंत्रालय के पत्र दिनांक **28.6.2004** के जवाब में, चंडीगढ़ प्रशासन, गृह विभाग ने अपने पत्र दिनांक **23.7.2004** के माध्यम से अपनी टिप्पणियाँ संप्रेषित की हैं जो इस प्रकार हैं:-

(i) नियमित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के गठन की कार्यवाही तेजी से की जा रही है।

(ii) पीईसी सोसायटी की वित्त समिति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नामितों को शामिल करने का सुझाव बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की पहली बैठक में रखा जाएगा।

(iii) एमओए /उपनियमों में किसी भी संशोधन के लिए चंडीगढ़ प्रशासन की मंजूरी पीईसी सोसायटी द्वारा ली जाएगी और भारत सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं हो सकती है।

(2) इस मंत्रालय के 28 जून, 2004 के पत्र के जवाब में, चंडीगढ़ प्रशासन, गृह विभाग ने अपने पत्र दिनांक 23 जुलाई, 2004 के माध्यम से अपनी टिप्पणियाँ संप्रेषित की हैं जो इस प्रकार हैं:-

(i) नियमित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के गठन के लिए शीघ्र कार्रवाई की जा रही है।

(ii) मानव संसाधन विकास मंत्रालय/विश्वविद्यालय अनुदान के नामांकित व्यक्तियों को शामिल करने का सुझाव पीईसी सोसायटी की वित्त समिति में कमीशन को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की पहली बैठक में रखा जाएगा।

(iii) एमओए/उपनियमों में किसी भी संशोधन के लिए चंडीगढ़ प्रशासन की मंजूरी पीईसी सोसायटी द्वारा ली जाएगी, और भारत सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं हो सकती है।

3. चंडीगढ़ प्रशासन से दिनांक 8-9 जुलाई 2004 की एक अधिसूचना संख्या 11/23/152-आईएच(2)-2004/12566 भी प्राप्त हुई है, जिसमें पीईसी, चंडीगढ़ को उसकी वर्तमान स्थिति से "पूरी तरह से वित्त पोषित स्वायत्त निकाय" में शामिल किया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन के "एक विभाग" की। अधिसूचना के अनुसार पीईसी का प्रशासन पीईसी सोसायटी में निहित होगा।

सूचना एवं आगामी आदेश हेतु प्रस्तुत।

एसडी/29.7.2004

हम यूटी प्रशासन को सूचित कर सकते हैं कि जब तक उपरोक्त पैरा 1 में सुझाए गए अनुसार एमओए /पीईसी के नियमों में संशोधन नहीं किया जाता है, तब तक एमओए /पीईसी के नियमों को सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया जा सकता है।

एसडी/-

30.7.2004।"

(30.7.2004 के बाद कोई नोटिंग देखी या उत्पादित नहीं की गई है)।

20. याचिका की सुनवाई के दौरान विभिन्न सीएम द्वारा दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखने के लिए दायर किया गया था, साथ ही विभिन्न आदेशों द्वारा समय-समय पर मांगे गए हलफनामे भी दायर किए गए थे और कहा गया था कि उक्त दस्तावेजों को सभी अपवादों के अधीन रिकॉर्ड पर ले लिया गया है। यह देखा जा सकता है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने **8 जुलाई, 2004** को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके माध्यम से यह देखा गया था कि शैक्षणिक सत्र **2004-05** के लिए, पीईसी संबद्धता के उद्देश्य से पंजाब विश्वविद्यालय के तत्वावधान में कार्य करना जारी रखेगा। और शैक्षणिक कार्यक्रम आदि और एक डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में पीईसी के नए शैक्षणिक कार्यक्रम अगले शैक्षणिक सत्र **2005-06** से लागू किए जाएंगे। ऐसा लगता है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने वस्तुतः समझ लिया था कि पीईसी का डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में वास्तविक, तथ्यात्मक और व्यावहारिक कामकाज शैक्षणिक सत्र **2004-05** के लिए संभव नहीं हो सकता है। विभिन्न पैराग्राफों का संदर्भ देकर पूर्वोक्त अधिसूचना में निहित और प्रदान किए गए कुछ प्रावधानों पर ध्यान देना उचित होगा। पैरा **2, 30, 38** और **39** के विशिष्ट संदर्भ की आवश्यकता है जो इस प्रकार है :

XX XX XX XX

2. चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज को उसके बजट में वर्ष **2004-05** के लिए योजनागत और गैर-योजना व्यय दोनों के लिए पहले ही स्वीकृत अनुदान सहायता **1 अक्टूबर 2004** से लागू हो जाएगी। चालू वित्तीय वर्ष के लिए पंजाब इंजीनियरिंग

कॉलेज को योजना और गैर-योजना दोनों मदों में, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा **30.9.2004** तक संबंधित लेखा प्रमुखों के तहत संचालित किया जाना जारी रहेगा। हालाँकि, वर्ष **2005-06** के बाद से, चंडीगढ़ प्रशासन, हर साल, वर्ष के दौरान गैर-योजना और योजना व्यय के बराबर अनुदान सहायता के रूप में पेंशन के कारण होने वाले व्यय को छोड़कर, ब्लॉक अनुदान प्रणाली के आधार पर धनराशि स्वीकृत करेगा। **2003-04**. सोसायटी एक वार्षिक बजट तैयार करेगी और अनुदान सहायता के रूप में धन के आवंटन के लिए इसे प्रशासन को प्रस्तुत करेगी। प्रशासन किसी विशेष वर्ष में दी जाने वाली सहायता अनुदान की राशि को बढ़ा या घटा सकता है। भविष्य में सहायता अनुदान के निर्धारण का मार्गदर्शन करने वाले नियमों को प्रशासन द्वारा पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज सोसायटी के परामर्श से और यदि आवश्यक हो तो भारत सरकार की मंजूरी के साथ अलग से अंतिम रूप दिया जाएगा।

XXX XXX XXX XXX

30. पीईसी सोसायटी और सोसायटी के तहत कार्यरत सभी विभागों/निकायों में पदों के आरक्षण के संबंध में, आरक्षण के वही प्रावधान लागू होंगे जो चंडीगढ़ प्रशासन और इसके विभिन्न विभागों में प्रचलित हैं। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज या उसके अधीन विभागों में विभिन्न सीटों पर प्रवेश के संबंध में भी, आरक्षण के संबंध में वही प्रावधान लागू होंगे जो वर्तमान में पीईसी में प्रचलित हैं।

XXX XXX XXX XXX

38. **2004-05** के शैक्षणिक सत्र के लिए, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज संबद्धता और शैक्षणिक कार्यक्रमों आदि के उद्देश्य से पंजाब विश्वविद्यालय के तत्वावधान में कार्य करना जारी रखेगा। एक डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के नए शैक्षणिक कार्यक्रम यहां से लागू किए जाएंगे। अगला शैक्षणिक सत्र अर्थात् **2005-2006**। एनआरआई सीटों/एनआरआई प्रायोजित सीटों की शुरुआत और छात्रों के लिए

ट्यूशन फीस में संभावित वृद्धि की संभावना के संबंध में, मामला पीईसी सोसायटी पर छोड़ दिया जाएगा।

39. वित्तीय नियम और सेवा नियम और चंडीगढ़ प्रशासन के अन्य सभी नियम/दिशानिर्देश और अन्य सभी नियम/दिशानिर्देश जो वर्तमान में लागू हैं, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज सोसाइटी द्वारा पालन किया जाएगा जब तक कि सोसाइटी द्वारा विशेष रूप से अन्यथा प्रदान न किया गया हो। एसोसिएशन का ज्ञापन और उपनियम।

XXX XXX XXX XXX "

21. यह देखा जा सकता है कि प्रस्ताव का नोटिस **6** अप्रैल **2004** के आदेश के तहत जारी किया गया था जो **9.4.2004** को वापस किया जा सकता है। पीईसी में छात्रों के प्रवेश से जुड़ा मामला होने के कारण छोटी तारीख दी गई थी। लिखित बयान प्राप्त होने पर, प्रतिवादियों के वकील **9** अप्रैल, **2004** के अंतरिम आदेश को हटाने के लिए दबाव डाल रहे थे, जिसके तहत दिनांक **10.2.2004** के आक्षेपित आदेश, प्रतिलिपि अनुलग्नक पी-**3** की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि छात्रों के प्रवेश के लिए काउंसलिंग आयोजित की जानी थी। इस प्रकार, **4** अगस्त **2004** को अंतरिम आदेश पारित किया गया, जो इस प्रकार है:-

आंशिक रूप से दलीलें सुनी गईं। इस स्तर पर, श्री शर्मा प्रतिवादी नंबर **1** और **2** की ओर से जवाब दाखिल करने में सक्षम होने के लिए स्थगन चाहते हैं। वे **9.8.2004** तक विपक्षी वकील को एक अग्रिम प्रति के साथ ऐसा कर सकते हैं। आगे कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा।

11.8.2004 को स्थगित।

हम यह भी निर्देश देते हैं कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज को डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने से संबंधित रिकॉर्ड अनुबंध पी-**11** के माध्यम से उन प्रावधानों के विवरण के साथ अदालत में पेश किए जाएंगे जिनके

तहत डीम्ड विश्वविद्यालय की घोषणा के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

हम यह भी निर्देश देते हैं कि **9.8.2004** के लिए निर्धारित काउंसलिंग यह मानकर चलेगी कि **85%** कोटा स्थानीय उम्मीदवारों के लिए और **50%** बाहरी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है, लेकिन उसका परिणाम अगले आदेश तक घोषित नहीं किया जाएगा। दस्ती। "

22. 14 अगस्त 2004 का हलफनामा, प्रोफेसर वेद प्रकाश, सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा दायर किया गया है और उन्होंने हमारे कुछ प्रश्नों का स्पष्ट रूप से उत्तर दिया है, जो इस प्रकार है:

XXX XXX XXX XXX

2. यूजीसी के विद्वान वकील द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस माननीय न्यायालय ने यूजीसी को निम्नलिखित बिंदुओं को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है:

- (a) क्या यूजीसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए जारी दिशानिर्देश वैधानिक प्रकृति के हैं या नहीं?
- (b) क्या ये दिशानिर्देश बाध्यकारी हैं?
- (c) **21 दिसंबर 1985** की अधिसूचना वर्तमान मामले पर लागू है या नहीं?

इस संबंध में, यह निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:

- (a) दिशानिर्देश वैधानिक प्रकृति के नहीं हैं बल्कि प्रशासनिक निर्देश के रूप में हैं।
- (b) ये दिशानिर्देश उन सभी मानित विश्वविद्यालयों पर बाध्यकारी हैं, जिन्हें मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है और उन्हें उक्त दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

(c) विनियम यूजीसी (संस्थानों की स्थापना और रखरखाव), 1985 दिनांक 21 दिसंबर, 1985 यूजीसी अधिनियम की धारा 12 ccc के तहत संस्थानों की स्थापना और रखरखाव के लिए है। इन संस्थानों को अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र कहा जाता है। इन विनियमों के तहत, यूजीसी विश्वविद्यालयों के समूह के लिए सामान्य सुविधाएं, सेवाएं और कार्यक्रम प्रदान करने के लिए संस्थानों की स्थापना करता है।

"यह उल्लेख करना उचित हो सकता है कि अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी से अलग हैं। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा यूजीसी अधिनियम की धारा 3 के तहत यूजीसी की सिफारिशों पर दिया जाता है। 1956।"

23. श्रीमती निर्मलजीत कौर ने तर्क दिया कि पीईसी चंडीगढ़ को निस्संदेह यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार एक डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित किया गया है, लेकिन, ऐसी अधिसूचना जारी करना अकेले उक्त संस्थान को सभी प्रकार से कार्यात्मक डीम्ड विश्वविद्यालय नहीं बनाता है। यूजीसी ने 3 जुलाई, 2003 के पत्र के माध्यम से पूर्वोक्त अधिसूचना जारी करने से पहले सिफारिश की थी और उसमें भी टिप्पणियां की गई थीं और क्या उन्हें तर्क के लिए पूर्व-आवश्यकताओं के रूप में लिया जा सकता है और उन अधिसूचनाओं को पूरा किए बिना यूजीसी अधिनियम की धारा 3 के तहत भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा यदि अधिसूचना पूर्वापेक्षाओं के अनुपालन के बिना जारी की गई है, तो कार्यान्वयन के लिए मार्जिन संबंधित तिमाहियों को देना पड़ सकता है। क्या अधिसूचना जारी करने का मतलब यह होगा कि कुछ आवश्यकताएँ, जैसा कि पूर्वोक्त किया गया है, संबंधित हलकों से भविष्य में पूर्ति की सहमति मात्र से पूरी हो गई मानी जा सकती हैं और बाकी को पूरा करने की अनुमति दी जाएगी और डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा और इसे अधिसूचना के अनुसार स्वीकार किया जाना चाहिए।

भारत संघ, यूजीसी और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा प्रस्तुत उत्तरों के अवलोकन से पता चलता है कि डीम्ड विश्वविद्यालय को कार्यात्मक बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज एमओए को आज तक मंजूरी नहीं दी गई है। उत्तरदाताओं ने यह दावा करके गलत रुख अपनाया है कि एमओए को मंजूरी दे दी गई है। भारत संघ ने इस न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत करते समय ऐसा बयान दिया है, लेकिन, तथ्य यह नहीं है, जैसा कि उत्तर प्रस्तुत करते समय यूजीसी द्वारा अपनाए गए कमजोर रुख से स्पष्ट है। कुछ स्थानों पर ऐसा ही रुख भारतीय संघ द्वारा भी अपनाया गया है। जबकि, चंडीगढ़ प्रशासन ने यूटी चंडीगढ़ के निवासियों के लिए सीटों के आरक्षण के संबंध में एक स्पष्ट और सकारात्मक रुख अपनाया है, यानी एमओए के आधार पर आरक्षण कम कर दिया गया है। उनके संदर्भ में, विशेष रूप से एमओए के पैरा 6 का संदर्भ दिया गया है, जिसे उनके द्वारा अपने उत्तर में पुनः प्रस्तुत किया गया है। यदि एमओए को मंजूरी नहीं दी गई है, तो एमओए के पैरा 6 पर कैसे भरोसा किया जा सकता है और विवादित आदेश/अधिसूचना दिनांक **10.2.2004** जारी की जा सकती है। उत्तर "नहीं" होना चाहिए। यदि ऐसा है, तो उपरोक्त अधिसूचना टिकाऊ नहीं होगी और रद्द किये जाने योग्य है।

24. आगे यह तर्क दिया गया है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने वर्तमान याचिका दायर करने के बाद, दिनांक **8.7.2004** को एक और अधिसूचना जारी करके अपने आदेश दिनांक **10.2.2004** की रक्षा करने का एक हताश प्रयास किया है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि कार्यान्वयन डीम्ड विश्वविद्यालय को व्यावहारिक और तथ्यात्मक रूप से कार्यान्वित करना संभव नहीं हो सकता है और इसलिए, इस तरह के शासन को सत्र **2005-06** से लागू किया जाएगा, लेकिन शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए पीईसी वर्तमान सत्र **2004-05** के दौरान पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध रहेगा। यदि ऐसा है, तो क्या एमओए में निहित शर्त का हिस्सा विवादित आदेश जारी करके लागू किया जा सकता है जिसे अभी तक अनुमोदित किया जाना है।

25. यह भी तर्क दिया गया है कि जहां तक पीईसी को डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में दी गई मान्यता का सवाल है, तो इसे चुनौती नहीं दी जा रही है, लेकिन इसे डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में वास्तविक,

तथ्यात्मक और व्यावहारिक रूप से कार्य करने के लिए जो कार्य करने या करने की आवश्यकता है उसमें संबंधित तिमाहियों द्वारा समय की आवश्यकता हो सकती है। यदि ऐसा है, तो डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में पीईसी के व्यावहारिक कामकाज के लिए आवश्यकताओं का अनुपालन किए बिना दिनांक **10.2.2004** की अधिसूचना/आदेश जारी करने की कोई जल्दी नहीं थी। विशेष रूप से, जब चंडीगढ़ प्रशासन का रुख यह है कि चंडीगढ़ के स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण को **85%** से घटाकर **50%** करना एमओए पर निर्भर है और इसमें निहित है, तो इस संबंध में, पैरा **6** का विशेष संदर्भ दिया गया है। वही, लेकिन, एमओए को अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है। जबकि, चंडीगढ़ प्रशासन इस आधार पर आगे बढ़ रहा है कि एमओए को मंजूरी दे दी गई है जैसा कि लिखित बयान में उनके कथनों में कहा गया है, जो तथ्य गलत है। जब मूल दस्तावेज़, जिसके आधार पर चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा रुख अपनाया गया है, को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, तो विवादित आदेश/अधिसूचना जारी करना टिकाऊ नहीं होगा और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

26. दूसरी ओर, चंडीगढ़ प्रशासन के विद्वान वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री राजीव आत्मा राम ने आग्रह किया है कि पीईसी को दी गई डीम्ड यूनिवर्सिटी की स्थिति को इस न्यायालय के समक्ष किसी ने चुनौती नहीं दी है यानी धारा **3** के तहत जारी अधिसूचना को चुनौती नहीं दी गई है। यूजीसी अधिनियम दिनांक **16.10.2003**. इस प्रकार, अधिसूचना जारी होने और पीईसी को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किए जाने पर, एक बात का निष्कर्ष निकलेगा कि आवश्यक सभी कार्यों का अनुपालन किया गया माना जाएगा। इस संबंध में उन्होंने इस पर निर्भरता जतायी है:

(i) पुनः: बॉम्बे राज्य बनाम पांडुरंग विनायक और अन्य, एआईआर 1953 सुप्रीम कोर्ट 244।

सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने देखा कि अधिसूचना जारी होने के बाद कानून की व्याख्या करते समय काल्पनिक कल्पना का पालन किया जाना चाहिए। इस संबंध में उद्धरण इस प्रकार है:-

"जब कोई क़ानून अधिनियमित करता है कि कुछ ऐसा किया गया माना जाएगा, जो वास्तव में और सत्य नहीं किया गया था, तो न्यायालय यह सुनिश्चित करने का हकदार और बाध्य है कि वैधानिक कल्पना का सहारा किन उद्देश्यों के लिए और किन व्यक्तियों के बीच लिया जाना है और इसका पूरा प्रभाव होगा वैधानिक कथा को अवश्य दिया जाना चाहिए और इसे इसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाना चाहिए। **(एक्स पैरी वॉल्टन में लॉर्ड जस्टिस जेम्स : इन रे: लेवी, (1881) 17 अध्याय डी. 746 पृष्ठ 756(ए)** पर। यदि धारा 15 में उल्लिखित वैधानिक कल्पना के उद्देश्य को ध्यान में रखा जाए, तो यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि अधिसूचना का शाब्दिक अर्थ उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है, तो उस कल्पना का उद्देश्य पूरी तरह से विफल हो जाएगा। **ईस्ट एंड वेलिंग्स कंपनी लिमिटेड बनाम फिन्सबरी बरो काउंसिल, 1952 एसी 109 , लॉर्ड एस्किवथ** ने टाउन एंड काउंटी प्लानिंग एक्ट, 1947 के प्रावधानों से निपटते समय उसी सिद्धांत का संदर्भ दिया और इस प्रकार देखा:

"यदि आपको मामलों की एक काल्पनिक स्थिति को वास्तविक मानने के लिए बाध्य किया जाता है, तो आपको निश्चित रूप से, जब तक कि ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, वास्तविक परिणामों और घटनाओं की भी कल्पना करनी चाहिए, जो कि यदि मामलों की कथित स्थिति वास्तव में अस्तित्व में थी, तो अनिवार्य रूप से प्रवाहित होनी चाहिए इसके साथ... क़ानून कहता है कि आपको मामलों की एक निश्चित स्थिति की कल्पना करनी चाहिए; यह नहीं कहता है कि ऐसा करने के बाद, जब उस स्थिति के अपरिहार्य परिणामों की बात आती है तो आपको अपनी कल्पना को भ्रमित करना चाहिए या अनुमति देनी चाहिए "।

इस प्रकार अध्यादेश को निरस्त करने के लिए लागू धारा **25**, बॉम्बे जनरल क्लॉज एक्ट के प्रावधानों की घोषणा करने और उस अध्यादेश को एक अधिनियम मानने का परिणाम यह है कि अधिसूचना में जहां भी "अध्यादेश" शब्द आता है, उस शब्द को अधिनियम पढ़ा जाना चाहिए "।

27. आगे यह तर्क दिया गया है कि राज्य के भीतर निवास की आवश्यकता और संस्थागत प्राथमिकता के आधार पर थोक आरक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती है और ऐसा कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद **14** का उल्लंघन होगा। इन्हीं आधारों पर भारत सरकार द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है और चंडीगढ़ यूटी कोटे के लिए आरक्षित सीटों को **85%** से घटाकर **50%** कर दिया गया है। यह तर्क दिया गया है कि एमओए या अन्य जगहों पर निहित शर्तों के अनुसार, यूटी प्रशासन स्थानीय लोगों के कोटा को **85%** से घटाकर **50%** करने के अपने अधिकार में था। तर्क के समर्थन में, विद्वान वकील ने **डॉ. प्रदीप जैन आदि बनाम भारत संघ और अन्य**, एआईआर **1984** सुप्रीम कोर्ट **1420** मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया है। फैसले के पैरा **10, 13, 18, 20** और **21** का संचयी अंश इस प्रकार है:-

"कोई भी कहीं भी, विनम्र या उच्च, कृषि या शहरी पुरुष या महिला, चाहे उसकी भाषा या धर्म, जन्म स्थान या निवास कुछ भी हो, सांस्कृतिक विकास, प्रशिक्षण सुविधा, विशेषज्ञता के लिए किसी भी धर्मनिरपेक्ष शैक्षिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए समान अवसर या रोजगार पाने का हकदार है। यह कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण के मूल सिद्धांत के विपरीत होगा यदि कोई नागरिक अपने निवास के कारण राज्य ए में है, जो आम तौर पर मामलों की समानता में उसके जन्म का परिणाम होगा उस राज्य के भीतर स्थित स्थान पर शिक्षा या उन्नति का अवसर होना चाहिए, जो किसी अन्य नागरिक को

इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वह राज्य बी का निवासी है। देश भर में शिक्षा और उन्नति के अवसर की समानता के माध्यम से सार्वभौमिक उत्कृष्टता का दर्शन और व्यावहारिकता का हिस्सा है। इसलिए, प्रयास हमेशा देश के सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करके तकनीकी संस्थानों और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ और सबसे मेधावी छात्र का चयन करना होना चाहिए और कोई भी नागरिक गंभीर नुकसान के बिना वैध रूप से ऐसा नहीं कर सकता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, हमारे संस्थागत ढांचे में एक बाहरी व्यक्ति के रूप में माना जाता है। हालाँकि, योग्यता के आधार पर चयन के सिद्धांत से विचलन उचित रूप से किया जा सकता है। संविधान के तहत समानता की अवधारणा एक गतिशील अवधारणा है। यह समानता और सुरक्षात्मक भेदभाव की हर प्रक्रिया को अपने दायरे में लेता है। अमिट सामंती छाप और लाइलाज वास्तविक असमानता वाले एक पदानुक्रमित समाज में, यह सुझाव देना बेतुका है कि समूह की अक्षमताओं को खत्म करने और सामूहिक समानता को बढ़ावा देने के प्रगतिशील उपाय इस आधार पर समानता के विरोधी हैं कि प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह से योग्यता के आधार पर अवसर की समानता का हकदार है। उसके द्वारा प्राप्त अंकों से आंका जाता है। अवसर की समानता केवल कानूनी समानता का मामला नहीं है। इसका अस्तित्व केवल विकलांगताओं की अनुपस्थिति पर नहीं बल्कि क्षमताओं की उपस्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए, जहां असमानता है, वास्तव में, कानूनी समानता हमेशा इसे बढ़ाती है। कानून में समानता से वास्तविक समानता उत्पन्न होनी चाहिए, कानूनी समानता को अंततः वास्तविक समानता में अपना उद्देश्य ढूंढना चाहिए। इसलिए, राज्य को उन लोगों

को, जो अपने धन, शिक्षा या सामाजिक परिवेश में तथ्यात्मक रूप से असमान हैं, निर्दिष्ट क्षेत्रों में समान बनाने के उद्देश्य से प्रतिपूरक राज्य कार्रवाई का सहारा लेना चाहिए। इसलिए, मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की योजना योग्यता के आधार पर चयन के सिद्धांत से हट सकती है, जहां असमान लोगों के बीच अवसर की वास्तविक समानता लाने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक है । इस प्रकार, व्यापक आधार पर चिकित्सा प्रवेश के अवसरों को बराबर करने और वास्तविक और औपचारिक नहीं, वास्तविक और केवल कानूनी समानता लाने के लिए निवास की आवश्यकता के आधार पर आरक्षण का एक निश्चित प्रतिशत वैध रूप से बनाया जा सकता है। गणना में किए गए आरक्षण के प्रतिशत में उसी विश्वविद्यालय की प्री-मेडिकल परीक्षा के लिए पीयूसी उत्तीर्ण करने वाले या राज्य में मेडिकल कॉलेजों के शैक्षिक भीतरी इलाकों की स्कूल प्रणाली से योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए संस्थागत आरक्षण भी शामिल हो सकता है। उद्देश्य, राज्य, बोर्ड से संबद्ध स्कूलों और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के बीच अंतर नहीं होना चाहिए। हालाँकि, ऐसा आरक्षण किसी भी स्थिति में वैध रूप से किए गए अन्य प्रकार के आरक्षणों को ध्यान में रखते हुए खुली सीटों की कुल संख्या के **70** प्रतिशत की बाहरी सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। तदनुसार, कुछ राज्य सरकारों द्वारा राज्य के भीतर "अधिवास" या निवास की आवश्यकता के आधार पर या राज्य के लिए विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए संस्थागत प्राथमिकता के आधार पर हमारे छात्रों को छोड़कर थोक आरक्षण दिया गया है। योग्यता की परवाह किए बिना इन आवश्यकताओं को पूरा करना संविधान के अनुच्छेद **14** का उल्लंघन होने के कारण

असंवैधानिक और शून्य है। यह बात बीडीएस कोर्स पर भी लागू होती है।"

28. यह भी तर्क दिया गया है कि शीर्ष अदालत ने समय-समय पर टिप्पणी की है कि राज्य के भीतर निवास की आवश्यकता या संस्थागत प्राथमिकता के आधार पर आरक्षण प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार, मौजूदा मामले में, पीईसी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के बाद, सीटें तदनुसार कम कर दी गई हैं, इसलिए, दिनांक **10.2.2004** का आदेश, कानून के तहत टिकाऊ है, क्योंकि यह किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं है। याचिकाकर्ताओं को कथित तौर पर भारत के संविधानके तहत संरक्षित किया गया है। पूर्वोक्त निर्णय और विशेष रूप से पैरा **22** और **23** का संदर्भ दिया गया है जिसका सार इस प्रकार है:-

"जहां तक एमएसएमडी और इस तरह के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश का सवाल है, यह अत्यधिक वांछनीय होगा कि राज्य के भीतर निवास की आवश्यकता या संस्थागत प्राथमिकता के आधार पर कोई आरक्षण प्रदान न किया जाए। लेकिन, व्यापक विचारों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा में अवसर की समानता और संस्थागत निरंतरता का अपना महत्व और मूल्य है, हालांकि राज्य के भीतर निवास की आवश्यकता स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश में आरक्षण का आधार नहीं होगी, वर्तमान परिस्थितियों में सीटों का एक निश्चित प्रतिशत आरक्षित किया जा सकता है संस्थागत प्राथमिकता के आधार पर इस अर्थ में कि एक छात्र जिसने मेडिकल कॉलेज या विश्वविद्यालय से एमबीबीएस पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है, उसे उसी मेडिकल कॉलेज या विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्राथमिकता दी जा सकती है, लेकिन इस तरह के आरक्षण के आधार पर संस्थागत प्राथमिकता किसी भी स्थिति में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उपलब्ध खुली सीटों की कुल संख्या के **50** प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह एमडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के संबंध में

समान रूप से लागू होना चाहिए। हालाँकि, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के संबंध में भी, जहाँ तक न्यूरोसर्जरी और कार्डियोलॉजी जैसी सुपर स्पेशलिटी का सवाल है, संस्थागत प्राथमिकता के आधार पर भी कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए और प्रवेश पूरी तरह से योग्यता के आधार पर दिया जाना चाहिए"।

29. आगे यह तर्क दिया गया है कि एक बार स्थिति परिभाषित हो जाने के बाद, व्यावहारिक कामकाज के उद्देश्य से इसके कार्यान्वयन में कुछ समय लग सकता है, जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने काफी हद तक स्वीकार किया है। यदि ऐसा है, तो पीईसी को डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी किए गए आगामी आदेशों, अधिसूचनाओं को उसके अनुरूप माना जाएगा। यह ध्यान में रखा जा सकता है कि अखिल भारतीय आधार पर डीम्ड विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में **50%** सीटों की पेशकश की शर्त को पीईसी को उक्त दर्जा दिए जाने से पहले चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पूरा किया जाना आवश्यक था। **9** सितंबर, **2003** के उसके उत्तर से यह स्पष्ट है, जिसकी प्रति भारत संघ द्वारा अनुलग्नक आरआई/III के रूप में संलग्न की गई है कि यूटी कोटा के लिए सीटों को **85%** से घटाकर **50%** करने की मंजूरी चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पहले ही दे दी गई थी। . चूंकि मूल अधिसूचना दिनांक **16.10.2003** पर सवाल नहीं उठाया गया है, जो राज्य कोटा (चंडीगढ़ कोटा) की कटौती पर आधारित है, याचिकाकर्ता के मुंह से दिनांक **10.2.2004** के संचार पर सवाल उठाना झूठ नहीं होगा, जो कि है उपरोक्त अधिसूचना के प्रचार-प्रसार में एक कृत्य के अलावा और कुछ नहीं है। यह स्थापित कानून है कि अधिसूचना के प्रगति और प्रसार में जो कुछ भी किया जाता है, जिसे चुनौती नहीं दी जाती है, ऐसी कार्रवाइयां मुख्य अधिसूचना के वास्तविक इरादे के अनुरूप होंगी और हैं। इस प्रकार, बाद के ऐसे आदेशों और अधिसूचनाओं को चुनौती नहीं दी जा सकती है और उन्हें कानून के तहत बताए गए किसी भी कथित अधिकार का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। इस तथ्य को याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हुए स्वीकार किया है कि ऐसी शर्तें, आदेश और अधिसूचनाएं **2005-06** के सत्र में लागू या लागू की जा सकती हैं, न कि वर्तमान सत्र में। इस प्रकार, याचिका

खारिज करने योग्य है क्योंकि दिनांक **10.2.2004** के आदेश/संचार में कोई कानूनी खामी नहीं पाई गई है या पाई जा सकती है क्योंकि राष्ट्रीय परीक्षण, जो विधिवत आयोजित किया गया है के आधार पर अखिल भारतीय आधार पर स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में **50%** सीटें पेश की जानी हैं।

30. भारत संघ और यूजीसी के विद्वान स्थायी वकील श्री एसके शर्मा ने चंडीगढ़ प्रशासन के तर्कों को अपनाया है।

31. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और संबंधित दलीलों और प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में संलग्न दस्तावेजों और संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी अधिसूचनाओं का भी अध्ययन किया है और हमने प्रतिवादी नंबर **1, 2 3** और **4** के मूल रिकॉर्ड का भी अवलोकन किया है।

32. हमने इस याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विचार किया है। स्वीकृत तथ्य यह है कि पीईसी को "डीम्ड यूनिवर्सिटी" का दर्जा देने के लिए यूजीसी अधिनियम, **1956** की धारा **3** के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। यह भी स्वीकार किया गया मामला है कि उपरोक्त प्रावधान के अनुपालन में, यूजीसी द्वारा की गई सिफारिश पर ऐसी स्थिति प्रदान की गई है, जिसे यहां ऊपर देखा गया है। पक्षों के विद्वान वकील का कहना है कि डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने के बाद पीईसी वास्तव में, तथ्यात्मक और व्यावहारिक रूप से एक विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करने की स्थिति में नहीं है। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा यह बहुत ही निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया गया है कि पीईसी को स्वायत्त, प्रशासनिक, वित्तीय और हर तरह से एक विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करने में सक्षम होने से पहले कई कार्य हैं जिन्हें प्रतिबद्ध, पूरा करना और उनका अनुपालन करना आवश्यक है। हमें उन विनियमों से नहीं दिखाया गया है, जो यूजीसी द्वारा जारी किए गए हो सकते हैं, कि धारा **3** के तहत अधिसूचना जारी होने से पहले किसी संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय कहे जाने के लिए कौन सी पूर्व-आवश्यकताएं पूरी की जानी आवश्यक हैं। यूजीसी अधिनियम के हालाँकि, यह स्वीकार किया गया मामला है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) को यूजीसी के अवलोकन के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक था, जो एक डीम्ड विश्वविद्यालय/संस्थान के लिए कामकाज पूरा करने के लिए मैग्ना कार्टा है। दलीलों, पत्राचार और पेश की गई मूल फाइलों के

अवलोकन से एक बात स्पष्ट रूप से पता चलती है कि कोई भी पक्ष यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि एमओए को अंततः मंजूरी दे दी गई है या नहीं। भारत सरकार ने यह रुख अपनाया है कि एमओए को मंजूरी दे दी गई है, यह तथ्य संबंधित अधिकारी द्वारा दायर लिखित बयान से प्राप्त हुआ है। दूसरी ओर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक गैर-प्रतिबद्ध जवाब दिया है और दलील दी है कि भले ही एमओए को मंजूरी नहीं दी गई हो, स्थानीय लोगों (यूटी कोटा) के लिए सीटों का आरक्षण **85%** से घटाकर **50%** किया जा सकता है। इसलिए। चंडीगढ़ प्रशासन ने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया है कि एमओए को मंजूरी दे दी गई है और पैरा **6** का एक विशिष्ट संदर्भ देकर इसकी सामग्री पर बहुत अधिक निर्भरता बनाई गई है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि सीटों का आरक्षण **85%** से कम किया जाएगा। स्थानीय लोगों के लिए **50%** तक। उत्तरदाताओं, भारत सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और यूजीसी के संबंधित अधिकारियों ने हमें इस संबंध में उचित और ईमानदार सहायता नहीं दी थी, जैसा कि सरकार की मूल फाइलों के अवलोकन से स्पष्ट है। भारत सरकार और यूजीसी द्वारा उक्त दोनों उत्तरदाताओं के लिए स्थायी वकील श्री एस.के. शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया। हमने फाइलों से देखा है कि दिनांक **30.7.2004** की अंतिम नोटिंग तक, भारत सरकार ने एमओए की मंजूरी के संबंध में अपनी आपत्ति व्यक्त की है। यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को सूचित किया जाए कि जब तक सुझाव के अनुसार पीईसी के एमओए /नियमों में संशोधन नहीं किया जाता है, तब तक इसे भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में चंडीगढ़ प्रशासन को संबोधित दिनांक **4.8.2004** का एक पत्र फ़ाइल में है। यह स्पष्ट है कि डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में पीईसी का प्रभावी और व्यावहारिक कामकाज संभव नहीं हो सका है, हालांकि यह प्रयास किया गया था कि यह सत्र **2004-05** के लिए इसी तरह से काम करे। यह तथ्य यूटी चंडीगढ़ द्वारा **8 जुलाई 2004** को जारी की गई अधिसूचना से बहुत स्पष्ट है, जिसे अनुलग्नक आर-**3/4** के रूप में जोड़ा गया है। उक्त अधिसूचना के अवलोकन से पता चलता है कि पीईसी को सत्र **2004-05** के लिए पंजाब विश्वविद्यालय के तत्वावधान में संबद्ध रहने की अनुमति दी गई है और यह भी देखा गया है कि शैक्षणिक कार्यक्रमों आदि के लिए यह वस्तुतः पहले की तरह काम करना जारी रखेगा। यह भी उल्लेख किया गया है कि डीम्ड

विश्वविद्यालय के रूप में पीईसी के नए शैक्षणिक कार्यक्रम शैक्षणिक सत्र यानी **2005-06** से लागू किए जाएंगे। जहां तक पीईसी में फैकल्टी के पदों और अन्य पदों के आरक्षण का सवाल है, जिसे प्रशासन के अनुसार पीईसी सोसाइटी ने अपने कब्जे में ले लिया है, चंडीगढ़ प्रशासन में लागू और प्रचलित प्रावधानों को लागू कर दिया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि पीईसी को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने के बावजूद, इसके कामकाज को स्वायत्त-वित्तीय और हर तरह से स्वायत्त नहीं बनाया जा सका क्योंकि बजट में प्रावधानों को एक बार फिर से आवंटित किया गया है। यह अजीब बात है कि चंडीगढ़ प्रशासन को अच्छी तरह से पता था कि एमओए को मंजूरी नहीं दी गई है, जैसा कि भारत सरकार से उन्हें प्राप्त संचार से स्पष्ट है, लेकिन उन्होंने **10 फरवरी, 2004** को आदेश जारी करने का फैसला किया, जिसके आधार पर कोटा का आरक्षण स्थानीय लोगों के लिए **85%** से घटाकर **50%** कर दिया गया है, जिसे यूजीसी अधिनियम, **1956** की धारा **3** के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए पूर्व-आवश्यकता नहीं दिखाया गया है।

33. बेंच ने पक्षों के विद्वान वकील से एक स्पष्ट प्रश्न पूछा था कि यूजीसी द्वारा **3 जुलाई, 2004** के संचार के माध्यम से की गई सिफारिशों में शामिल टिप्पणियों को यूजीसी अधिनियम की धारा **3** के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए पूर्व-आवश्यकताएं कहा जा सकता है। उत्तर यह है कि ये पूर्व आवश्यकताएँ नहीं हैं। यह देखा जा सकता है कि स्नातक स्तर पर **50%** सीटें स्थानीय लोगों के लिए और **50%** अखिल भारतीय आधार पर उपलब्ध कराने की शर्त का उल्लेख भारत सरकार को पीईसी के मामले की सिफारिश करते समय की गई टिप्पणियों में मिलता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यूजीसी अधिनियम, **1956** की धारा **3** के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए यह पूर्व-आवश्यकता नहीं थी ।

34. यूजीसी अधिनियम की धारा **3** के तहत अधिसूचना जारी करने का मतलब यह होगा कि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुपालन और यूजीसी द्वारा की गई टिप्पणियों का संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुपालन किया गया माना जाएगा। और, इसलिए, स्थानीय निवासी के लिए सीटों की कटौती टिकाऊ है और केंद्र शासित प्रदेश ने **10 फरवरी, 2004** को जो

आदेश सही ढंग से जारी किया है, वह बिल्कुल भी सही नहीं है। पांडुरंग विनायक मामले (सुप्रा) में फैसले पर भरोसा किया गया है। हमें डर है कि उक्त निर्णय इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। यह उस अधिसूचना की व्याख्या नहीं है जो हमारे सामने उठाई गई है कि डीम्ड विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली वास्तव में, तथ्यात्मक और व्यावहारिक रूप से सवाल में है। एक बार, यह स्वीकार कर लिया गया है कि इन सभी तीन विशेषताओं को यूजीसी अधिनियम, **1956** की धारा **3** के तहत अधिसूचना जारी करने के आधार पर हासिल नहीं किया जा सकता है, यह स्वीकार करना बहुत अधिक होगा कि एक अवलोकन सीटों के आरक्षण को अनुपालन के रूप में लिया जाएगा और उनमें से बाकी कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं, उनका पालन किया जा रहा है या तदनुसार मार्ग प्रशस्त करने के लिए सक्षम अधिकारियों पर छोड़ दिया गया है। इस प्रकार, प्रतिवादी के विद्वान वकील का तर्क टिकाऊ नहीं है और इसलिए इसे खारिज कर दिया गया है।

35. यह तर्क भी टिकाऊ नहीं है कि राज्य के भीतर निवास की आवश्यकता और संस्थागत प्राथमिकता के आधार पर आरक्षण स्थानीय लोगों के लिए कोटा कम करने और बाहरी लोगों को देने के प्रशासन के अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकता है। चंडीगढ़ प्रशासन का यह मामला नहीं है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में प्रख्यापित/प्रावधानित नियमों के प्रावधानों और यूजीसी अधिनियम, **1956** की धारा **3** के तहत अधिसूचना दिनांक **10** फरवरी, **2004** के उल्लंघन से आदेश को जारी किया जा सकता है। केंद्र शासित प्रदेश के लिखित बयान के अवलोकन से पता चलता है कि एमओए में निहित शर्तों पर एक स्पष्ट और पर्याप्त भार रखा गया है , जैसा कि **9** सितंबर, **2003** को **24** जुलाई, **2003** के पत्र पर यूजीसी अधिनियम की धारा **3** के तहत अधिसूचना जारी होने से पहले इस संबंध में भारत सरकार को उनके जवाब से स्पष्ट है। हालाँकि यह रुख अपनाया गया है कि यूजीसी की सिफारिशें ऐसी अधिसूचना जारी करने के लिए पूर्व-आवश्यकताएं नहीं हैं, फिर भी एमओए की मंजूरी को दिनांक **10.2.2004** के विवादित आदेश को जारी करने का आधार बनाया गया है, जिसे वास्तव में अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया है। यदि किसी डीम्ड विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली सीधे तौर पर एमओए के तहत निहित चार्टर से संबंधित है, जिसके मॉडल का पालन किया जाना है, तो ऐसे चार्टर को संबंधित

अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किए बिना आदेश पारित करना प्रशासन के बस की बात नहीं है। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, चंडीगढ़ प्रशासन के वकील द्वारा संदर्भित और उपरोक्त निर्णय बिल्कुल भी लागू नहीं होते हैं।

36. यह तर्क कि याचिकाकर्ता दिनांक **10.2.2004** के आदेश को चुनौती देने के हकदार नहीं हैं, जो दिनांक **16.10.2003** की मूल अधिसूचना के प्रचार और कार्यान्वयन में पूरक है, जिसे चुनौती नहीं दी गई है, टिकाऊ नहीं होगा। निस्संदेह, मुख्य अधिसूचना हमारे सामने चुनौती नहीं है, लेकिन, किसी भी मामले में, यह सभी ने स्वीकार किया है कि डीम्ड विश्वविद्यालय को वास्तव में, तथ्यात्मक और व्यावहारिक रूप से क्रियाशील बनाने के लिए अंतराल अवधि की आवश्यकता होती है। हालाँकि, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा किए गए कृत्यों और दिए गए अनुमानों से पता चलता है कि पीईसी वर्तमान सत्र **2004-05** के लिए एक डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में पूर्ण परिप्रेक्ष्य में कार्य करने में सक्षम नहीं होगा, पीईसी पंजाब के तत्वावधान में कार्य करना जारी रखेगा। संबद्धता और शैक्षणिक कार्यक्रमों आदि के उद्देश्य से विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में नए शैक्षणिक कार्यक्रम अगले शैक्षणिक सत्र **2005-06** से लागू किए जाएंगे। यदि ऐसा है, तो जिस एकल अधिनियम के आधार पर वर्तमान सत्र **2004-05** के लिए स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित सीटें कम कर दी गई हैं, उसे **10** फरवरी **2004** के आक्षेपित आदेश के आधार पर कम नहीं किया जा सकता था, खासकर जब ऐसा हुआ हो एमओए को मंजूरी दिए बिना जारी किया गया है, जबकि ऐसा आदेश चार्टर यानी एमओए के पैरा **6** पर आधारित है।

37. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है। नतीजतन, याचिका स्वीकार की जाती है और विवादित आदेश दिनांक **10.2.2004** अनुलग्नक पी-3 को रद्द कर दिया जाता है और उसके अनुसार किए गए कृत्य (स्थानीय लोगों के लिए **85%** की सीमा तक यूटी कोटा) के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेंगे। यह देखा जा सकता है कि **4** अगस्त **2004** के हमारे आदेश द्वारा, हमने **9.8.2004** के लिए निर्धारित काउंसलिंग को इस आधार पर जारी रखने की अनुमति दी थी कि **85%** सीटें स्थानीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं और अब तक इसे बरकरार रखा जाएगा। जहां तक अखिल भारतीय आधार पर उम्मीदवारों का संबंध है,

काउंसलिंग में **50%** की सीमा तक की अनुमति दी गई थी, जिसे अब केवल **15%** तक ही ले जाया जाएगा, जैसा कि पहले मौजूद था।

36. फ़ैसला पूर्ण होने से पहले, हम कुछ मामलों में अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं। भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों ने अपने-अपने लिखित बयान दाखिल करके जिस तरह और तरीके से हमारी सहायता की है, उसे देखकर हमें वास्तव में दुख हुआ है। यह हमारे अनुरोध पर है कि भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक विस्तृत पैरावाइज उत्तर दाखिल किया है जिसमें स्पष्ट कथनों को एमओए की वीजा-विज़ मंजूरी दी गई है। इससे पहले, संबंधित अधिकारियों ने अपने लिखित बयानों में स्पष्ट रूप से कहा था कि एमओए को मंजूरी दे दी गई थी, जिसके कारण हमें भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रिकॉर्ड की मांग करनी पड़ी, जिसके अवलोकन से हमें पता चला कि एक स्पष्ट गलत बयान संबंधित अधिकारियों द्वारा दिया गया है। यह न केवल कर्तव्य की अवहेलना है बल्कि न्यायालय के समक्ष एक बेईमान बयान दिया गया है। यह सलाह दी जाती है कि संबंधित अधिकारी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही कर सकते हैं/शुरू कर सकते हैं। किसी भी मामले में, उन्हें न्यायालयों की सहायता के प्रयोजनों के लिए लिखित बयान दाखिल करते समय भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी दी जाती है। हम, न्यायालय उन बयानों पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं जो लिखित बयान दाखिल करने के माध्यम से सरकार द्वारा प्रकट किए जाते हैं।

39. भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ प्रशासन का आधिकारिक रिकॉर्ड संबंधित क्वार्टरों में पहुंचाने के लिए उनके संबंधित वकील को वापस कर दिया गया है। भुगतान पर दस्ती।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

उदित अग्रवाल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

करनाल, हरियाणा